

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकारश्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्रीश्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

संवेदना से सेवा

51 लाख
नए लोग
खाद्य सुरक्षा से जुड़े22 लाख
लोगों ने स्वेच्छा से
छोड़ा लाभ

- अब हर पात्र को मिलेगा अन्न
- खाद्य सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी चयन
- घर बैठे आवेदन, सरल प्रक्रिया
- कोई पात्र नहीं रहेगा वंचित



- गिव-अप अभियान बना संवेदनशील समाज की पहचान
- ज़रूरतमंदों को मिला खाद्य सुरक्षा का लाभ
- सामाजिक न्याय और पारदर्शिता को मिली गति
- जन भागीदारी से जन कल्याण

खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों को 4-IN-1 लाभ



प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
के तहत प्रति व्यक्ति प्रतिमाह
5 कि.ग्रा. निःशुल्क खाद्यान्न



मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना
के तहत परिवार को 450 रुपये में
प्रतिवर्ष 12 घरेलू गैस सिलेण्डर



मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना
में परिवार का 10 लाख रुपये तक
का निःशुल्क दुर्घटना बीमा कवर



मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना
में परिवार का निःशुल्क पंजीकरण एवं
25 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com



हिण्डौन सिटी

Rashtradoot

फोन:- 230200, 230400 फैक्स:- 07469-230600

वर्ष: 17

संख्या: 242

प्रभात

हिण्डौन सिटी, रविवार 6 जुलाई, 2025

पो. रजि.SWM-RJ-6069/2017-18

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

उद्धव ठाकरे-राज ठाकरे के पुनर्मिलन व एकता समारोह में कांग्रेस अनुपस्थित क्यों रही?

एन.सी.पी. की ओर से सुप्रिया सुले, वामपंथी दलों के नेता, किसान यूनियन के प्रतिनिधि, प्रोग्रेसिव बुद्धिजीवी व सिविल सोसायटी के एक्टिविस्ट भारी संख्या में मौजूद थे, इस समारोह में

5 साल की बच्ची से ज्यादाती के आरोपी को दस साल की सजा

जयपुर, 5 जुलाई। जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने करीब पांच साल की बच्ची के साथ ज्यादाती करने वाले अभियुक्त विमल कुमार को दस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी के.सी. अटवालिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने न केवल करीब पांच साल की बच्ची का अपहरण किया, बल्कि उसके साथ ज्यादाती भी की। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा

■ **पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने बालिका का अपहरण किया और ज्यादाती की।**

सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने अदालत को बताया कि 9 फरवरी, 2023 को पीड़िता अपने परिवार के साथ पड़ोसी के बेटे की शादी में गई थी। देर रात खेत से चिल्लाने की आवाज आई तो बालिका का पिता खेत पर पहुंचा तो वहां गांव के दो युवकों ने विमल को पकड़ रखा था। पृष्ठने पर बताया कि विमल उसकी पांच साल की बेटी को पास के सरसों के खेत में ले गया और ज्यादाती करने की कोशिश की। पीड़िता (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रोहित गोदारा के नाम पर 5 करोड़ की फिरोती मांगी

बीकानेर, 5 जुलाई (निर्स)। एक फाइनेंशियल कंपनी के सीईओ पीयूष श्रृंगारी से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर रोहित गोदारा बताया था। पुलिस ने सीईओ को सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही कॉल की छानबीन शुरू कर दी है। मामला जयनारायण व्यास थाने का है।

■ **एसपी ने फाइनेंशियल सर्विस के सीईओ की सुरक्षा में हथियार बंद पुलिस तैनात की।**

वैल्योनिफ फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीईओ पीयूष श्रृंगारी ने पुलिस को इस मामले की शिकायत की। एसपी कावेन्द्र सिंह सागर के आदेश पर सीईओ के घर और आसपास वर्दी व सामान्य वर्दी में हथियारबंद पुलिस तैनात की गई है। सीईओ ने रिपोर्ट में बताया कि 2 जुलाई की शाम को उनके पास बॉट्सएणू कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

■ **-जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 5 जुलाई। शिवसेना के संस्थापक परिवार के उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बहुप्रतीक्षित पुनर्मिलन ने महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन को हिला दिया है। इस घटनाक्रम ने राज्य में आशा और आशंका-दोनों को जन्म दिया है। जहां यह एकता पूरे महाराष्ट्र में एक मजबूत प्रतीकात्मक संदेश दे रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी की इस कार्यक्रम से स्पष्ट दूरी ने महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन के भीतर गहरे रणनीतिक समीकरणों और बढ़ती असहजता को उजागर कर दिया।
यह कार्यक्रम काफी धूमधाम से आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक जगत के कई नेताओं और हस्तियों ने भाग लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले, वामपंथी दलों के नेता, प्रमुख किसान संगठनों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील शिक्षाविद और सामाजिक

■ **राजनीतिक टीकाकार, इस समारोह की तुलना 1950 के दशक के संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन से कर रहे हैं जिसकी इतिश्री नये राज्य, 1960 में महाराष्ट्र के जन्म होने के बाद हुई थी।**
■ **राज ठाकरे ने अपनी पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन उत्तर भारत के महाराष्ट्र में बसे लोगों के खिलाफ आक्रामक रुख को आधार बनाकर किया था। कांग्रेस, राज ठाकरे की उस छवि को स्वीकार नहीं कर पा रही, विशेषकर, अब जबकि उत्तर भारत में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं तथा राज ठाकरे से गठबंधन को उत्तर भारत में समझाना आसान काम नहीं है। कांग्रेस उत्तर भारत में पुनः जीवित होने की महत्वाकांक्षा रखती है।**
■ **साथ ही, अगर उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे में सच्ची मित्रता हो जाती है तो कांग्रेस के लिए भारी खतरा है, दोनों भाईयों की मित्रता से महाविकास अघाड़ी गठबंधन में नये पावर समीकरण बनेंगे। जिसमें, कांग्रेस का महत्व घटने की भारी संभावना है।**

यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा विवाद को फिर से हवा दी

यूपी सरकार ने कांवड़ मार्ग पर खान-पान की दुकानों के मालिकों को पहचान उजागर करने का आदेश दिया है

■ **-श्रीनंद झा- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 5 जुलाई। हिंदू भावनाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक बार फिर कांवड़ यात्रा से पहले हिंदू-मुस्लिम विभाजन से राजनीतिक लाभ उठाने की रणनीति अपनाई है। यह यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है।
पिछले साल इसी तरह के आदेश को लेकर विपक्षी दलों और नागरिक समाज समूहों द्वारा किए गए भारी विरोध के बावजूद, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यह अनिवार्य कर दिया है कि कांवड़ मार्ग पर मौजूद सभी खाद्य प्रतिष्ठान अपना वैध खाद्य लाइसेंस और स्वामित्व विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करें।
हालांकि पिछले साल उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाली

■ **गत वर्ष भी यूपी सरकार ने ऐसा ही आदेश दिया था, पर, भारी विरोध के कारण उस पर रोक लगा दी थी।**
■ **यूपी के उपमुख्यमंत्री बुजेश पाठक ने कहा, हर खरीददार को यह जानने का हक है कि वह जिससे सामान खरीद रहा है, वह कौन है।**
■ **विपक्षी नेताओं ने यूपी सरकार पर धार्मिक ध्रुवीकरण करने की राजनीति का आरोप लगाया। असदुद्दीन औवैसी ने कहा, इतने सालों से यात्रा शांति से चल रही थी, अब अचानक से क्या हो गया है।**
खाद्य दुकानों के नाम प्रमुखता से प्रदर्शित करने के आदेश को वापस ले लिया था, इस साल राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने खुले तौर पर इस आदेश को उचित ठहराया है। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बुजेश पाठक ने सार्वजनिक रूप से कहा कि “हर खरीदार को यह जानने का अधिकार है कि वह किससे सामान

खरीद रहा है। यह नियम भी है। यदि उनसे नाम लिखने को कहा जा रहा है, तो इसमें क्या समस्या है?”
वरिष्ठ मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसा आदेश विवाद से बचने के लिए जारी किया गया है। “विभिन्न धर्मों की अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘नैशनल हैरल्ड को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, बेचने की नहीं’

कांग्रेस ने शनिवार को जवाब दिया कि पार्टी हैरल्ड की कम्पनी “एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड” (ए.जे.एल.) की सम्पत्ति नहीं बेचेगी

■ **-जाल खंबाता- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 5 जुलाई। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वह नैशनल हैरल्ड को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, ना कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को बेचने की।
एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) का आरोप है कि गांधी परिवार के पास यंग इंडियन नामक निजी कंपनी में 76 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी है, और इस कंपनी ने 90 करोड़ के ऋण के बदले एजेएल की संपत्तियों को धोखाधड़ी से अपने अधीन कर लिया।
वरिष्ठ अधिकता आर. एस. चीमा, जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ने शनिवार को कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) एजेएल की संपत्तियों को बेचने की नहीं, बल्कि उस संस्था को बचाने की कोशिश कर रही है, जो

■ **सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के वकील आर.एस. चीमा ने कहा, ए.जे.एल. की स्थापना 1937 में जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, रफी अहमद किदवाई आदि ने की थी। इस कम्पनी की आज़ादी के आंदोलन में अहम भूमिका थी। कांग्रेस पार्टी इसे बेचने के बजाय बचाने का प्रयास कर रही है।**
■ **चीमा ने कहा, एजेएल के मैमोरेन्डम ऑफ एसोसिएशन में साफ लिखा है, कम्पनी की नीति ही कांग्रेस की नीति होगी। यह कम्पनी प्रॉफिट के लिए नहीं बनी थी।**
■ **चीमा ने कहा, समस्या ए.जे.एल. को दिए गए कर्ज की वसूली नहीं, बल्कि ए.जे.एल. को पुनः पटरी पर लाने की है।**
■ **ज्ञातव्य है कि ईडी ने गांधी परिवार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी कम्पनी “यंग इंडियन” के मार्फत 90 करोड़ रुपए के कर्ज के एवज में ए.जे.एल. की सम्पत्तियों पर कब्जा कर लिया है।**

स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा रही है। चीमा ने यह जवाब विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत में पेश किया।
ईंडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, साथ ही सुमन दुबे, सैम पित्रोवा और निजी कंपनी यंग इंडियन पर 2,000 करोड़ से अधिक मूल्य की संपत्तियों धोखे से अधिग्रहित करने का आरोप लगाया है। ये संपत्तियाँ एजेएल की थीं, जो नैशनल हैरल्ड अखबार प्रकाशित करता था। चीमा ने अदालत में संवाल उठाया: “क्या मेरे मित्र (ईडी के वकील) बता सकते हैं कि उन्होंने एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) पेश करने से परहेज क्यों किया?”
उन्होंने बताया, “एजेएल की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा समाप्त हुई

धुवनेश्वर, 05 जुलाई। ओड़ीशा के पुरी में शनिवार को भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथयात्रा का भव्य समापन हुआ।

इस अवसर पर आध्यात्मिक उत्साह से सराबोर लाखों श्रद्धालु आज भगवान जगन्नाथ की ‘बाहुदा यात्रा’

■ **भगवान जगन्नाथ अपने भाई -बहिन के साथ गुंडिचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर लौट गए हैं। इस अवसर पर लाखों भक्तगण मौजूद थे।**

(वापसी रथ उत्सव) देखने के लिए तीर्थ नगरी पुरी में उमड़ पड़े। भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र के रथों को भक्तों द्वारा खींचा गया, जिससे पूरा भव्य मार्ग जय जगन्नाथ के नारों और झांझ की थाप के बीच गुंज उठा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सर्कार/स्थानीय निकायों/बैंकों आदि द्वारा जारी कोई प्रमाणपत्र: आम आदमी के लिए यह असंभव सी मांग है। जन्म प्रमाणपत्र, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय जन्म और मृत्यु पंजीयक द्वारा (बर्थ एण्ड डैथ एक्ट) , 1969 के तहत जारी किए जाते हैं, 18 साल पहले दुर्लभ थे। ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रक्रिया में पंचायत सचिव, ब्लॉक विकास अधिकारी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी शामिल होते हैं। शहरी क्षेत्रों में यह नगर निगम और परिषदों द्वारा पूरी होती है। नियमों के अनुसार, अगर समय पर रिपोर्ट किया गया हो तो जन्म प्रमाणपत्र जारी होने में कुछ ही दिनों का समय लगता है, लेकिन अगर देरी हो तो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

व्यक्ति के आवेदन से संतुष्ट होना चाहिए, यानी उसे भरोसा हो जाना चाहिए कि आवेदक भारतीय नागरिक है और मतदान के योग्य है। आयोर्ग ई.आर.ओ. को यह नहीं कह सकता कि सिर्फ यही दस्तावेज़ मान्य होंगे, अन्य प्रमाण भी मान्य हो सकते हैं। अगर वे ई.आर.ओ. को संतुष्ट करते हैं। लेकिन वास्तविकता में बिहार के सामाजिक-आर्थिक हालात को देखते हुए आम लोगों के लिए ये दस्तावेज़ जुटाना लगभग असंभव है। दस्तावेजों में शामिल है: सरकारी कर्मचारी/पेंशनधारकों का पहचान पत्र: बिहार जाति सर्वे 2022 के अनुसार केवल 20.49 लाख लोग सरकारी सेवा में हैं, जो राज्य की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.57 प्रतिशत है। 01.07.1987 से पहले भारत

■ **बिहार में ऐसे कुल मतदाता 2.93 करोड़ हैं।**
■ **बिहार की प्रशासनिक काम करने की रफ्तार से नये मतदाता काफी आशंकित हैं कि क्या वे समय रहते ये ग्यारह दस्तावेज़ सरकार से प्राप्त कर पायेंगे।**
■ **इसी आशंका के कारण वोटर लिस्ट रिविज़न को “वोट बंदी” का नाम दिया गया है. सोशल मीडिया में एलोकप्रिय “नोट बंदी” लागू की थी तथा कोविड की बाद स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से भारत में स्वयमेव “देश बंदी” लागू हुई थी।**

नामावली अधिकारियों (ई.आर.ओ.) को देता है कि वे तय करें कि कौन मतदाता सूची में शामिल किया जाए। चुनाव आयोग सिर्फ दिशानिर्देश जारी कर सकता है, लेकिन यह तय करना कि कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे, यह अधिकार ई.आर.ओ. के पास है। इसलिए, ई.आर.ओ. को किसी

चुनाव आयोग ने 24 जून और 30 जून को जारी दो बयानों में इस रिविज़न (पुनरीक्षण) के पीछे के कारण बताए गए हैं: “विदेशी अवैध प्रवासियों के नामों का सूची में होना,” “बार-बार का पलायन,” “युवाओं का मतदान के योग्य होना,” और “मृत्यु की रिपोर्ट न होना।”
हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये 11 दस्तावेजों की सूची केवल एक उदाहरण है इसका मतलब यह नहीं कि केवल यही दस्तावेज़ मान्य हैं, अगर किसी के पास इनमें से कोई दस्तावेज़ नहीं है तो भी वो अन्य दस्तावेज़ दिखाकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं। यह इसलिए संभव है क्योंकि भारत का जन प्रतिनिधत्व अधिनियम, 1950 यह अधिकार निर्वाचक

■ **-डॉ. सतीश मिश्रा- -राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**
नई दिल्ली, 05 जुलाई। चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में स्पेशल इन्टेन्सिव रिविज़न (एस.आई.आर.) करने का निर्देश जारी किया था, कथित रूप से अपात्र नामों को हटाने और केवल पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करने के उद्देश्य से।
चुनाव आयोग द्वारा बिहार में मतदाताओं के स्पेशल रिविज़न के मूल में 24 जून को दिया गया वह आदेश है, जिसमें कहा गया है कि जिन लोगों का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, जिनकी संख्या अनुमानतः 2.93 करोड़ है, उन्हें वोट देने की पात्रता साबित करने के लिए 11 में से कम से कम एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा।

■ **रामबन जिले में उस समय अमरनाथ यात्रियों के चार बसों आपस में टकरा गई जब एक बस का ब्रेक फेल हो गया।**

के निकट ब्रेक फेल होने के कारण वाहन का नियंत्रण खो दिया। इस हादसे में कम से कम 36 लोग घायल हो गये। उन्होंने कहा कि पुलिस, अर्धसैनिक बल और स्थानीय लोगों के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत बचाव अभियान शुरू किया तथा घायलों को अस्पताल पहुँचाया। सभी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

CM K

⊕

⊕

⊕

CM K

का झांसा देकर देह शोषण करने लगा।
 लम्बे समय तक देह शोषण करने पर
 बेटी का जन्म हुआ। आरोप है कि घोखे
 ने रखते हुए आरोपित ने बेटी के बर्ण
 सर्टिफिकेट पर पिता का गलत नाम
 लिखवा दिया। कुछ समय पहले
 शादीशुदा होने के साथ ही आरोपित के
 जालसाजी कर बर्ण सर्टिफिकेट पर फेक
 पिता नाम अंकित थायाने का पता चला।
 इस संबंध में पीडिता थाने पहुंची।

राज्यपाल ओम माथुर व मुख्यमंत्री ने बालोतरा शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम का शुभारंभ किया

इस कार्यक्रम में सर्वे करके ड्रॉप आउट व नामांकन से वंचित बालिकाओं की पहचान कर विद्यालय भेजा जाएगा

बालोतरा/जयपुर, 5 जुलाई। सिक्किम के राज्यपालक ओम प्रकाश माथुर ने शनिवार को बालोतरा के ग्राम पादरू में मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम (बीडीईटी) के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा अपनी मातृभूमि के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयास प्रारंभ किए गए हैं उससे बालक-बालिकाओं एवं युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। इस फाउंडेशन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों को वित्तीय मदद भी उपलब्ध करवायी गई है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षा के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाकर हर सामाजिक बुराई का अंत किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा 88 हजार 800 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं साथ में इंटरनेट कनेक्शन निशुल्क दिए गए हैं। इसके साथ ही पुस्तकालयों को 43 लाख पुस्तकें पहुंचाई गईं।

शर्मा ने कहा कि मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा जिला शिक्षा परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में शिक्षा एवं कौशल के लिए महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। इसमें घर-घर



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को जोधपुर के शेरगढ़ में दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने ऊंट की सवारी की।

सर्वे कर ड्रॉपआउट और नामांकन से वंचित बालिकाओं की पहचान कर उनका विद्यालयों में नामांकन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल शिक्षा तक ही नहीं बल्कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने योग्य

बनाने तक है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने बालोतरा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया है।

पूर्व में सिक्किम के राज्यपाल

- सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर तथा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अंत्योदय पखवाड़े के तहत ग्राम पादरू में लगे शिविर का अवलोकन किया व लाभार्थियों से संवाद किया।

ओम प्रकाश माथुर एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा के अंतर्गत पादरू में आयोजित शिविर का अवलोकन किया तथा विभिन्न विभागों की स्टॉल पर लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी प्रेमलता को चैक एवं रेखा को गोद-भराई किट दिया।

इस अवसर पर पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, उद्योग राज्यमंत्री के.के.विश्वनोई, सांसद उम्मेदराम बेनीवाल, सुधीर गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे।

‘राहुल के फोटो वाले सैनेटरी पैड का वितरण ‘‘फेक न्यूज’’ है’

नयी दिल्ली, 05 जुलाई। कांग्रेस ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी-भाजपा सेंनेटरी पैड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का फोटो छापकर फर्जी वीडियो चला रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसलिए इस मुद्दे पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा भाजपा और उनके लोग एक फेक वीडियो चला रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी जी की फोटो एक सेंनेटरी पैड पर लगी हुई है।

यह पूरी तरह से फेक है-इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भाजपा नफरत में इतना गिर गई कि बहन-बेटियों को भी नहीं बख्खा रहे हैं और उसको लेकर भी फर्जी न्यूज फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं।

- कांग्रेस ने यह दावा करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा यह फर्जी वीडियो चला रही है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेगी।

कांग्रेस नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि सेंनेटरी पैड पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का चित्र छपा गया है और भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसे लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

‘मैं 30-40 साल और जिंदा रहूंगा’

- सूत्रों के अनुसार अमेरिका के न्याय विभाग ने नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी की गिरफ्तारी सीबीआई व ईडी के आग्रह पर की है। नेहल पर अपने भाई के अपराध के सबूत छिपाने का आरोप है।

तालमेल किया जाएगा।

नेहल मोदी की गिरफ्तारी को 13 हजार करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी सफलता माना जा रहा है।

धर्मशाला, 05 जुलाई। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपने 90वें जन्मदिन की पूर्व संस्था पर शनिवार को धर्मशाला के मकलोटगंज में स्थित मुख्य मंदिर त्सुगलाखांग में आयोजित एक विशेष प्रार्थना समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने अपनी सेहत और लंबी उम्र को लेकर चल रही अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उनके पास अवलोकितेश्वर (करण के बौद्ध देवता) का आशीर्वाद है और वह अगले 30-40 साल तक लोगों की सेवा करना चाहते हैं। दलाई लामा ने समारोह में मौजूद 15,000 से ज्यादा भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, मुझे कई संकेत मिले हैं कि अवलोकितेश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने अब तक अपनी पूरी कोशिश की है और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अभी 30-40 साल और रिऊँगा। आपकी दुआओं का फल मुझे मिला है। उन्होंने यह भी बताया कि चुपचप से ही उन्हें लगता था कि उनका अवलोकितेश्वर से गहरा नाता है। हंसते हुए उन्होंने कहा, मैं 130 साल से ज्यादा जीना चाहता हूं ताकि बुद्ध धर्म और तिब्बत के लोगों की सेवा और कर सकूँ। हाल ही में दलाई लामा के उत्तराधिकारी की घोषणा को लेकर कई अफवाहें उड़ रही थीं, खासकर इसलिए क्योंकि उनका 90वां जन्मदिन नजदीक आ रहा था।

‘नैशनल हैरल्ड को ...

- ईडी इस मामले में सोनिया व राहुल से पूछताछ कर चुका है। ईडी की कार्यशील में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी व स्वीर्गीय मोतीलाल वोरा, स्व. आंस्कर फर्नांडिस के भी नाम हैं।

प्रतिशत शेरार है।

इससे पहले शुक्रवार को, वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोनिया गांधी की ओर से अपनी दलीलें पूरी कीं।

3 जुलाई को, वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन ने आरोपपत्र की वैधता के मुद्दे पर दलील देते हुए कहा कि गांधी परिवार यंग इंडियन के लाभार्थी मालिक है और अन्य शेरारधारकों की मृत्यु के बाद उन्होंने इस पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया।

ईडी ने गांधी परिवार और अन्य के खिलाफ धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपपत्र दाखिल किया है।

इस आरोपपत्र में सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटैक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड के नाम भी शामिल हैं।

5 साल की बच्ची ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) के पिता को खेत से पीड़िता के कपड़े और चप्पल मिली। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को घटना के बारे में जानकारी दी। वहीं अभियुक्त ने कहा कि उसे प्रेमिका में झूठा फंसाया गया है।

अब तक 25

हजार श्रद्धालुओं ने अमरनाथ के दर्शन किए

नई दिल्ली, 5 जुलाई। अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह चरम पर है। यात्रा के चौथे दिन तक 25 हजार श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। हर हर महादेव और बम-बम भोले के जयकारों के बीच हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि खबर है कि गर्मी के प्रभाव से बर्फ से निर्मित होने वाला शिवलिंग अब धीरे-धीरे पिघलने भी लगा है।

जानकारी के मुताबिक, जम्मू से करीब 7,000 श्रद्धालुओं का एक और जत्था शनिवार को रवाना हुआ। अब तक

- चौथे दिन सात हजार यात्री अमरनाथ के लिए रवाना हुए।

कुल 30 हजार से अधिक श्रद्धालु कश्मीर पहुंच चुके हैं। नुनवान बेस कैम्प से भी आज श्रद्धालुओं का एक नया जत्था रवाना हुआ। जानकारी के मुताबिक, आज श्रद्धालु भगवती नगर आधार शिविर से दो काफिलों में रवाना हुए।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा यात्रा को हरी झंडी दिखाए जाने के बाद से अब तक कुल 25,528 श्रद्धालु जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए घाटी की ओर खाना हो चुके हैं।

खास बात यह है कि पहले ऐसा लग रहा था कि पहलगाम हमले के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।

‘लड़ाई और बंटवारा तो हर घर में होता है’

राबड़ी देवी ने बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार व पार्टी से निकाले जाने पर टिप्पणी की

पटना, 5 जुलाई। तेज प्रताप यादव को लालू परिवार और राजद से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने पर पहली बार राबड़ी देवी ने बयान दिया है। शुक्रवार राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राबड़ी देवी ने तेज प्रताप यादव विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी सहित राजद के सभी बड़े नेता मौजूद थे।

इस कार्यक्रम को मंच से संबोधित करते हुए राबड़ी देवी ने तेज प्रताप विवाद पर कहा, “छोटा घर हो या बड़ा घर में, सबके घर में लड़ाई है, सबके घर में बंटवारा है भाई-भाई में। इस कार्यक्रम में लालू यादव को फिर से निर्विरोध राजद का राष्ट्रीय

रुट में आंशिक बदलाव से कुंभलगढ़ में मुहर्रम विवाद सुलझा

भविष्य में किले में धार्मिक आयोजन पूर्व अनुमति व पुरातत्व के दिशा निर्देश के अनुसार ही होंगे

- समझौते के बाद दो दिन से चल रहा विरोध प्रदर्शन बंद हुआ।
- केलवाड़ा कस्बे के बाजार खुले।

उदयपुर, 5 जुलाई (कांस)। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ दुर्ग में मोहर्रम पर ताजिए के जुलूस को लेकर पिछले दो दिन से चल रहा विवाद शनिवार को समाप्त हो गया। उपखंड कार्यालय कुंभलगढ़ में प्रशासन, हिंदू संघर्ष समिति और जनप्रतिनिधियों के बीच हुई समझौता वार्ता में सहमति बन गई। तय हुआ कि इस बार मोहर्रम के जुलूस के पूर्व निर्धारित रुट में थोड़ा बदलाव किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार बैठक में निर्णय हुआ कि भविष्य में दुर्ग परिसर या उसके भीतर किसी भी धार्मिक आयोजन की अनुमति प्रशासन की स्वीकृति और पुरातत्व विभाग की गाइडलाइन के अनुरूप दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि मोहर्रम जुलूस को लेकर हिंदू संगठनों द्वारा दो दिन तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। शुक्रवार को केलवाड़ा बस स्टैंड और प्रताप चौराहे पर सैकड़ों लोगों ने टायर जलाकर भारतीय पुरातत्व विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उपखंड कार्यालय के बाहर पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों का पुतला भी फूँका गया। विरोध के कारण केलवाड़ा कस्बे के बाजार बंद कराए गए थे जो अब समझौते के बाद पुनः खुल गए हैं।

वार्ता में विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़, एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम

आकांशा दुबे, तहसीलदार बाबूलाल नारनौलिया, एडिशनल एसपी महेंद्र पारीक, डीएसपी ज्ञानेंद्र सिंह, थानाधिकारी विशाल गवारिया और हिंदू संघर्ष समिति के प्रतिनिधि शामिल रहे। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक रजनीश शर्मा समेत पांच सदस्यों ने वार्ता में हिस्सा लिया।

विवाद को लेकर हिंदू संघर्ष समिति का कहना था कि जब भी हिंदू समाज द्वारा दुर्ग परिसर में धार्मिक आयोजन की अनुमति मांगी जाती है तो भारतीय पुरातत्व विभाग शासकीय स्वीकृति का हवाला देकर मना कर देता है। जबकि वर्षों से मोहर्रम, बारावफात और छड़ी जुलूस बिना अनुमति के निकाले जाते रहे हैं। इसी भेदभाव को लेकर समिति ने विरोध जताया था। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि अब सभी धार्मिक आयोजन प्रशासन और पुरातत्व विभाग की पूर्व अनुमति व दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही संपन्न होंगे।

मोहर्रम का जुलूस भी इस बार निर्धारित रुट से थोड़ा संक्षिप्त करते हुए निकाला जाएगा, ताकि सभी पक्ष संतुष्ट रहे और क्षेत्र में सद्भावना बना रहे।

‘देखना मोदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) पेरू जैसे अन्य साझेदारों के साथ भी इसी तरह की वार्ताएं चल रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) तभी संभव है जब दोनों पक्षों को समान रूप से लाभ हो।

गोयल ने आगे कहा, “मुक्त व्यापार समझौता तभी संभव है जब पारस्परिक लाभ हो। भारत कभी भी किसी समयसीमा या दबाव के आधार पर व्यापार समझौते में शामिल नहीं होता। कोई समझौता तभी स्वीकार किया जाता है जब वह पूरी तरह परिपक्व हो, अच्छी तरह से बातचीत की गई हो और राष्ट्रीय हित में हो।”

सड़क हादसे ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। उन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। खान ने बताया कि सभी तीर्थयात्रियों को मामूली चोटें आई हैं। इस मामले में आगे की जांच चल रही है।

राबड़ी देवी ने बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार व पार्टी से निकाले जाने पर टिप्पणी की

इसमें तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी देनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं करते हैं। रोजाना तेजस्वी से पूछते हैं कि कब क्या हो रहा है।

तेज प्रताप पर केवल राबड़ी देवी का ही बयान सामने आया है। लालू यादव और तेजस्वी का कोई बयान सामने नहीं आया है। मालूम हो कि कथित गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ वाली तस्वीर सामने आने के बाद तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी और परिवार से 6 साल से निष्कासित कर दिया था।

पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया के अलावा, मीडिया से हुई बातचीत में भी माता-पिता को भगवान

मानने की बात कही है। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि तेजस्वी को सीएम बनाना है।

रोहित गोदारा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) गैंगस्टर रोहित गोदारा बताते हुए 5 करोड़ की फिरीती मांगी थी। उसने कहा था कि यदि रुपए नहीं दिए तो उनके पूरे परिवार को जान से मार देंगे। कॉल के दो मिनट बाद शाम 7:15 बजे एक वॉइस नोट भी मिला।

चार जुलाई को एक और वॉइस मैसेज भेजा गया जिसमें रुपए नहीं देने पर धमकी दी गई। सीईओ ने जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की।

उद्धव ठाकरे-राज... तहमाचल में भारी बारिश से अब तक 7 2 की मौत, 3 7 लापता

बादल फटने और भारी बारिश से हिमाचल में भारी तबाही हुई है

- हिमाचल में बादल फटने की 21 घटनाएं हुई हैं, उसकी वजह से राज्य भर में बाढ़ आई हुई है।
- मौसम विभाग ने एक बार फिर रैड अलर्ट जारी किया, जिससे लोगों में भारी चिंता है।

से अलर्ट है। साथ ही उन्होंने राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने की भी बात कही है।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने की करीब 19 घटनाओं और इसके बाद अचानक आई बाढ़ के कारण व्यापक तबाही हुई है। इन घटनाओं में 72 लोगों की मौत

हो चुकी है और 37 लोग लापता हैं। अलर्ट की चेतावनी ने एक बार फिर चिंता को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के 3 जिलों में 6 जुलाई के लिए रैड अलर्ट की चेतावनी दी है और अन्य जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

24 जून को चुनाव आयोग द्वारा जारी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) प्रक्रिया लंबी हो जाती है, जिसमें हलफनामा और देरी हो जाने पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का आदेश भी लेना पड़ सकता है। बिहार इस मामले में बहुत कमजोर रिकॉर्ड रखता है।

साल 2000 में, जब भारत का रजिस्ट्रार जनरल डेटा रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था, बिहार में सिर्फ 1.19 लाख जन्मों का पंजीकरण हुआ, जो उस साल अनुमानित जन्मों का सिर्फ 3.7 प्रतिशत था। बिहार में जन्म पंजीकरण की दर धीरे-धीरे बढ़ी, लेकिन 2007 में भी, जो लोग इस वर्ष 18 वर्ष के होकर 2025 में मतदान का पात्र बनें, केवल 7.13 लाख जन्म पंजीकृत हुए, जो उस साल अनुमानित जन्मों का एक-छठा था।

पासपोर्ट की मांग, एक और दस्तावेज है, जो अजीब है, क्योंकि 2023 तक बिहार में वैध पासपोर्टों की संख्या सिर्फ 27.44 लाख थी, जो

कुल आबादी का लगभग 2 प्रतिशत ही थी।

मैट्रिक या शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जो मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी होते हैं: सी.बी.एस.सी., आई.सी.एस.सी. और बिहार राज्य बोर्ड जैसे बोर्ड इन्हें देते हैं। बिहार जाति समर्थ 2022 के अनुसार राज्य की केवल 14.71 प्रतिशत आबादी कक्षा 10 उत्तीर्ण है। यह दर और भी कम है क्योंकि राज्य में ड्रॉप-आउट दर 26 प्रतिशत (कक्षा 6-8) है, जैसा कि शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने 3 फरवरी, 2025 को लोकसभा में बताया।

स्थायी निवास प्रमाणपत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहा जाता है, यह प्रमाणित करता है कि आवेदक स्थायी निवासी है। इसके लिए आवेदक को आधार, राशन कार्ड, वोट आईडी, मैट्रिक प्रमाणपत्र और स्थायी निवास का हलफनामा प्रस्तुत करना होता है; फॉर्म में सी.डी.ओ. या कार्यपालक

मजिस्ट्रेट को जमा करना होता है। इसमें 15 दिनों तक समय लग सकता है, और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

वन अधिकार प्रमाणपत्र, प्राप्त करने हमारे पास विविध जनजातीय मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में इस अधिनियम के तहत केवल 4,696 दाखिले प्राप्त हुए, जिनमें से केवल 191 को प्रदान किया गया और 4,496 दाखिले अस्वीकृत कर दिए गए।

ओ.बी.सी./एस.सी./एस.टी. या किसी भी जाति का प्रमाणपत्र, जो सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है: बिहार जाति सर्वे 2022 के अनुसार, बिहार की कुल आबादी 113.07 करोड़ थी। इसमें से: ओ.बी.सी. 3.54 करोड़ (27 प्रतिशत), ई.बी.सी. 4.70 करोड़ (36 प्रतिशत), एस.सी. 2.6 करोड़

(20 प्रतिशत), एस.टी. 22 लाख (1.6 प्रतिशत) लेकिन इनमें से कितनों को इन जाति प्रमाणपत्रों का लाभ मिला, इसका कोई आंकड़ा मौजूद नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति इनमें से कोई एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता, तो चुनाव आयोग के निर्देश धारा 5बी के अनुसार, संबंधित अधिकारी “संदिग्ध विदेशी नागरिकों” के मामलों को नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत काबिल प्राधिकारी के पास भेज सकते हैं।

चुनाव आयोग ने पूरी प्रक्रिया को मतदाताओं के अनुकूल बनाने की इच्छा व्यक्त की अपील की नहीं माना।

चुनाव आयोग की इस पहल को सोशल मीडिया पर बोटबंदी कहा जा रहा है, जैसे 2016 की नोटबंदी और कोविड-19 के समय की देशबंदी।

बिहार में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में होने हैं।